**कश्मीर के बारे में अमरीका की राय**

3903. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1993 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "कश्मीर इज डिस्प्यूटिड टेरिटरी : यू० एस० ऑफिशियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार ने गत दो माह से कश्मीर विवाद के बारे में अपनी राय बदल ली है;

(ग) यदि नहीं, तो तथ्य क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अमरीकी सरकार द्वारा कश्मीर पर कायम उक्त राय तथ्यों पर आधारित नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीका सरकार से अपनी राय तथ्यों के आधार पर कायम करने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो अब अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार को सूचित की गई अमरीका की स्थिति यह है कि अमरीका वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कश्मीर को विवादास्पद प्रदेश मानता है । हाल ही में अमरीका ने अपनी नीति में एक यह नई बात जोड़ी है कि वह यह चाहता है कि कश्मीरी लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच यह समस्या शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जानी चाहिए । यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस प्रक्रिया में अमरीका की सहायता चाहते हों तो वह सहायता करने के लिए तैयार है ।

(घ) और (ङ) कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की वास्तविकताओं तथा भारत में आतंकवाद की सहायता करने तथा उसे दुष्प्रेरित करने में पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में सरकार अमरीका की सरकार को बराबर अवगत कराती रही है। सरकार यह बात जोर देकर कहती रही है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है ।

(च) अमरीका की सरकार ने यह कहा है कि अमरीका को यह बात तय नहीं करनी है कि कश्मीरियों के विचारों को किस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिए । अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि अमरीका इस बात पर बराबर निगाह रख रहा है कि पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर अमरीका को जो चिंता है उसे दूर करने में पाकिस्तान क्या कर रहा है । बताया जाता है अमरीका ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि यदि उसका सकारात्मक रवैया बरकरार नहीं रहता, अथवा यदि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सरकारी मदद प्रत्यक्षतः अथवा गैर-सरकारी स्रोतों के जरिये किसी रूप में फिर से शुरू की जाती है तो अमरीका के विदेश मंत्री को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजकी राज्य के रूप में सूचीबद्ध करने में कोई संकोच नहीं होगा ।

**चार 'दक्षेस' देशों के साथ बातचीत**

3904. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदियों पर पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करके इस संपूर्ण क्षेत्र को विकसित करने की संभावनाओं को मूर्तरूप देने तथा सात दक्षेस देशों में से चार देशों को लाभान्वित करने की दृष्टि से बांगलादेश, भूटान, नेपाल और भारत के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है तो क्या सरकार भविष्य में इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) से (ग) पन-बिजली परियोजनाएं लगाने के संबंध में बांगलादेश, भूटान, नेपाल और भारत के बीच कोई विचार-विमर्श तो नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने अनेक पन-बिजली परियोजनाओं के संबंध में संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए हैं और आपसी लाभ के लिए कुछ परियोजनाएं क्रियान्वित भी की हैं ।

सरकार आपसी लाभ की पन-बिजली परियोजनाएं संबंधित देशों के सहयोग से स्थापित करने को महत्व प्रदान करती है ।

**Ex-Ambassador's Link with Dawood Ibrahim**

3905. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an ex-Ambassador in U.S.A. was discredited for his links with Dawood Ibrahim and Win Chadha.

(b) whether it is a fact that normally a diplomat is not assigned to the same country twice;

(c) if so, why this ex-Ambassador with a dubious record is being sought to be reassigned to the U.A.E. and

(d) whether any step will be taken by Government to prevent such reassignment and bring to book those responsible for attempt to send him back to U.A.E. as India's Ambassador?

THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) No Sir.

(b) Postings of officers on diplomatic assignments are based on functional requirements and there is no restriction on officers being posted to the same country more than once if it is functionally desirable to do so.

(c) and (d) Question does not arise.

3906. *[Transferred to 26th August, 1993]*

**देश में दुग्ध-उत्पादन**

3907. **डा० जितेन्द्र कुमार** जैन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गत वर्षों के दौरान दूध के उत्पादन में भारी वृध्दि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में दूध पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता में भी अब वृध्दि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के रूप में दूध पर आधारित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो उस लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा ऐसे एकक स्थापित करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का निर्णय किया गया है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण करके विभिन्न दुग्ध-उत्पाद तैयार करने वाले कुल कितने औद्योगिक एकक कार्यरत थे ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई)**: (क) जी, हां। दुग्ध उत्पादन 1987-88 में 46.7 मिलियन टन था जो 1992-93 में बढ़कर 58.6 मिलियन टन हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दुग्ध उत्पाद तैयार करने को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कुटीर स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध एवं आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त में संगठित सेक्टर में 74 यूनिट थे जो विभिन्न दुग्ध-उत्पाद तैयार करने के लिए दुग्ध प्रसंस्करण में लगे हुए थे।

**Italian company setting up Candies and Chewing-gum Units**

*3908. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Italian Company is setting up Candies and Chewing-gum Units in the country and expected to go in production by January, 1994;

(b) if so, whether the Company is entering into the Indian market in a joint venture, if so, the details thereof; and

(c) if not, what are its likely implications/impacts on the indigenous industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) M/s. Perfetti SPA, Italy have been granted approval to set up a plant for manufacturing chewing-gum and toffees with 51% foreign equity, amounting to Rs. 9.69 crores in the paid-up capital of Rs. 19 crores. The company has reported that this plant is expected to go into production in the first quarter of 1994. The company has an obligation to export products of the value of at least Rs. 42 crores over a period of seven years.

**उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन**

3909. **श्री हरि वल्लभ यादव**: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निवेश द्वारा किन-किन उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई)**: (क) से (ग) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में कुछ सेक्टरों से संबंधित अध्ययन उपलब्ध है परन्तु इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में पूंजीनिवेश की गुंजाइश का आकलन करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। फिर भी खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में ऐसे अध्ययन करने के लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों, दूसरे संस्थानों एवं संगठनों को सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार

* Previously Unstarred Question 3224, transferred from 19th August, 1993.